DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED--- NEW DELHI SATURDAY JUNE 25, 2022

.com नई दिल्ली, 25 जून, 2022 दैनिक जागरण | 5

भ्रष्टाचार मामले में एलजी ने कानूनगो को किया निलंबित

चिराग दिल्ली में जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग स्थित डीडीए की जमीन को गलत तरीके से बेचने के आरोप में हुई कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: भ्रष्टाचार पर उपराज्यपाल (एलजी) का चाबुक जारी है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने हौजखास में जमीन को गलत तरीके से बेचने के आरोप में शुक्रवार को एक और अधिकारी को निलंबित कर दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन को गलत तरीके से नाम कर देने पर कानूनगो पर यह कार्रवाई की गई है। एलजी दो दिन पहले भी चार अधिकारियों को निलंबित कर चुके हैं।

हौजखास क्षेत्र के सब-रजिस्ट्रार डीसी साहू को एक निजी व्यक्ति की मिलीभगत से डीडीए की प्राइम लोकेशन की जमीन को ट्रांसफर करने के लिए, राजस्व रिकार्ड की जालसाजी से जुड़े गंभीर कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले में दो दिन पहले ही निलंबित किया गया था, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा सके। अब इस क्षेत्र के रिकार्ड रूम प्रभारी और कानूनगो रमेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। बता दें कि चिराग दिल्ली में जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग पर एक प्राइवेट पार्टी को कई करोड़ की जमीन दी गई। इसमें क्षेत्र के तत्कालीन कानूनगो की भूमिका संदिग्ध मिली है।

एलजी को सांसदों और विधायकों से इस सब-रजिस्ट्रार डीसी साहू के बारे में कई शिकायतें मिल रही थीं। ये शिकायतें नागरिकों और समूहों की ओर से भी गई थीं। इस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिनमें संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए घूस की मांग, दस्तावेजों से छेड़छाड़ और मनमानी शामिल थी। यह आरोप एलजी के संज्ञान में लाए गए। जांच में पता चला कि मामले में सब-रजिस्ट्रार ने क्षेत्र के कानूनगो के साथ मिलीभगत करके जाली दस्तावेज बनाए थे।

Hindustan Times

5th official sacked for role in 'illegal sale of govt land'

NEW DELHI: A fifth official has been suspended on the directions of LG VK Saxena in connection with the illegal sale of prime Delhi Development Authority (DDA) land, people aware of the matter said.

"DC Saheo, sub-registrar 5A, Hauz Khas, has been suspended to facilitate a fair inquiry into the matter of grave misconduct and corruption involving forging of revenue records in connivance with a private individual to transfer prime DDA land worth several crores to a private party on Josip Broz Tito Marg in Chirag Delhi," an official from the LG's office said on Friday, and identified the suspended official as Ramesh Kumar, the then records room in-charge of the area. HTC

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 25 जून 2022

डीडीए की जमीन बेचने वाले अफसर नपे

उप राज्यपाल के आदेश पर हुई कार्रवाई ताकि मामले में निष्पक्ष हो सके जांच

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में डीडीए की जमीन से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मामले में हौज खास के सब-रजिस्ट्रार (5-ए) डीसी साहू, कानूनगो रमेश कुमार और रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि आगे निष्पक्ष जांच हो सके। इस मामले में मिली शिकायतों की जांच के बाद उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को दिया था।

उप राज्यपाल ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के इस गंभीर मामले में रेवेन्यू रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करके प्राइम लोकेशन पर स्थित डीडीए की करोड़ों रुपये की जमीन एक प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफर कर दी गई। एलजी को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कुछ सांसदों, विधायकों और स्थानीय लोगों की तरफ से इस संबंध में काफी शिकायतें मिली थीं। भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में न केवल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए भारी घूस मांगी गई थी, बल्कि दस्तावेजों में हेराफेरी और मनमानी करने की बात भी एलजी के नोटिस में आई।

सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला कि मौजूदा मामले में सब-रजिस्ट्रार साहू ने एरिया इंचार्ज कानूनगो और कुछ अन्य लोगों के साथ आपराधिक मिलीभगत से पहले दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया, जिसमें साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में जोसिफ ब्रोज टीटो मार्ग पर पर स्थित डीडीए की करीब 1250 वर्ग गज जमीन को फ्री होल्ड दिखाया। जनवरी 2022 में उस जमीन की सेल डीड भी रजिस्टर्ड कर दी। 17 जून को एलजी ने इस पूरे मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट अपनी अनुशंसा के साथ चीफ सेक्रेटरी को भेजी थी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने 21 जून को इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।

एक्शन

- दस्तावेजों में हेराफेरी करके किया था फर्जीवाड़ा
- सांसदों, विधायकों व लोगों से मिली थी शिकायतें

उप राज्यपाल के द्वारा लिए जा रहे एक्शन की बीजेपी ने सराहना की है। साथ ही दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एलजी की इस तरह की कार्रवाई भ्रष्टाचार को रोकने में रामबाण का काम करेगी। एलजी के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी अब तक दिल्ली सरकार के 4-5 अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर चुके हैं। इनमें अडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— दैनिक जागरण नई दिल्ली, 26 जून, 2022 —DATED—

टीओडी परियोजना पर तेजी से काम करें अधिकारी : एलजी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए और एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) के अधिकारियों के साथ शनिवार को कड़कड़डूमा में दिल्ली की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) परियोजना के लिए चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से अब तक के कार्य की रिपोर्ट ली और योजना पर तेजी से काम करने को कहा। यह भी कहा कि संरचनात्मक सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। टीओडी बहुमंजिला आवासीय परियोजना है। इसमें सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होंगी। दिसंबर, 2019 में इसके लिए आधारशिला रखी गई थी, पर कोरोना और प्रदूषण के कारण निर्माण शुरू होने में काफी देरी हो गई। आखिरकार सितंबर 2021 में 25.47 हेक्टेयर में इसका काम शुरू हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक यहां 30 प्रतिशत हरित क्षेत्र होगा। शेष हिस्से में 70 प्रतिशत आवासीय होगा। 20 प्रतिशत में वाणिज्यिक और 10 प्रतिशत में नागरिक सुविधाएं होंगी। इसमें एक 48 मंजिला टावर भी होगा। यह परियोजना अब सितंबर 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। एलजी ने कहा कि यहां बनने वाली इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएं। उन्होंने जलपूर्ति, यातायात प्रबंधन, बिजली की उपलब्धता आदि की योजना बनाकर इसको निर्माण के साथ-साथ लागू करने के आदेश भी दिए।

कड़कड़डूमा में शनिवार को टीओडी परियोजना का निरीक्षण करते एलजी वीके सक्सेना (हेलमेट पहने हुए) ● जी. राजनिवास

हिन्दुस्तान नई दिल्ली रविवार 26 जून 2022

डीडीए में 40 से अधिक विभाग घटाने की तैयारी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अपने विभागों में कटौती किए जाने की कवायद की जा रही है। इसके चलते डीडीए में हजारों पद कम किए जा सकते हैं।

दरअसल, डीडीए की ओर से अपने ज्यादातर कार्यों के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में डीडीए के जनता से जुड़े और विभागीय कार्यों को ऑनलाइन किया जा चुका है। ऐसे में डीडीए की ओर से कई विभागों का समायोजन और कई को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया से डीडीए की कार्यप्रणाली में भी बदलाव होगा। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। डीडीए द्वारा की जा रही कवायद को लेकर केंद्र सरकार की सहमति के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि ई-ऑफिस को अपनाने के बाद से डीडीए का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत कम हो गया, जबकि ई ऑफिस की संस्कृति का विस्तार होता गया। निजी बिल्डरों के मार्केट में आ जाने से फ्लैटों की मांग भी अब उतनी नहीं रह गई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के तहत डीडीए की 145 डिवीजन को 102 तक समेटने का प्रस्ताव है। छोटे पद लगभग खत्म करने और बड़े पदों को बढ़ाने की सोच है।

| सांध्य नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | 26 जून 2022

'30 जुलाई तक ऑनलाइन हो एमसीडी की हर सर्विस'

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एमसीडी को निर्देश दिए हैं कि वह पब्लिक से जुड़ी सभी सर्विसेज को 31 जुलाई तक ऑनलाइन कर दे। एमसीडी के अर्बन सर्विसेज की रिव्यू मीटिंग के दौरान एलजी ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पब्लिक से जुड़ी सर्विस जिसमें बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स, ई-म्यूटेशन, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, लेआउट अप्रूवल, लाइसेंस, कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज, एडवरटाइजमेंट और होर्डिंग फीस कलेक्शन, अंतिम संस्कार और कूड़े की गाड़ियों की ट्रैकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने सर्विस की प्रक्रिया को यूजर फ्रेंडली बनाने पर भी जोर दिया।

एलजी ने मीटिंग में कहा कि इस पहल का लक्ष्य है कि लोगों को अपने कामों के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर कम से कम लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डेटा से लिंक करना चाहिए। इन डिपार्टमेंट में फूड सिक्योरिटी, पेंशन, जच्चा-बच्चा लाभ और अन्य वेलफेयर स्कीम शामिल हैं। इससे यह फायदा होगा कि सीधे इन योजनाओं के लिए नाम अपने आप जुड़ जाएंगे या कट जाएंगे। इससे फर्जी लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। 26 प्रतिशत जन्म अभी भी घरों में हो रहे हैं। इस संख्या को देखने के बाद उन्होंने निर्देश दिए कि हर वार्ड की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि किस वार्ड में यह समस्या अधिक है।

टीओडी पर भी निर्देश

■ विस, नई दिल्ली: कड़कड़डूमा में चल रहे टीओडी प्रोजेक्ट में अब निर्माण के साथ-साथ बिजली-पानी और ट्रैफिक उपलब्ध करवाने के लिए एलजी वी. के. सक्सेना ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर एक व्यापक रणनीति योजना बनाएं, ताकि निर्माण के साथ-साथ इसे भी लागू किया जा सके।

वी. के. सक्सेना

एलजी ने शनिवार को इस प्रोजेक्ट का दौरा किया और अधिकारियों को इसे लेकर कुछ अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मजबूत रहे और भूकंप रोधी हो। इसके अलावा नागरिकों की सभी जरूरतों को लेकर एक संभावित योजना भी तैयार करें और इसी प्रोजेक्ट के साथ-साथ उसे लागू करें। उन्होंने डीडीए और एनबीसीसी के अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिल्ली की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) परियोजना का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करें। गौरतलब है कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से शहर के स्काईलाइन को बदलने के साथ पूर्वी दिल्ली में भी बदलाव होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE SUNDAY EXPRESS, JUNE 26, 2022

How DDA offered housing to Delhi's aspiring middle-class, set example for rest of India

ADRIJA ROYCHOWDHURY
NEW DELHI, JUNE 25

IN THE mid-1970s when Reena Ramachandran (81) was working in the Ministry of Science and Technology in the government of India, she came across an advertisement brochure of the Delhi Development Authority (DDA) announcing its first self-financing group housing scheme in Saket. The area was nothing more than large swathes of agricultural land at the time, and far away from Sardar Patel Marg, where she was living with her husband, who worked for the Railways department. But the scheme, said Ramachandran, was a great investment opportunity for "people like her".

"My husband and I were both government employees with limited means. It was difficult to buy land and build a house of your own in a city as expensive as Delhi," she explained. "The DDA scheme was within our reach to pay in instalments and we would not have to deal with any builder. The DDA itself was the builder." The fact that the house would be in a housing colony with security and all amenities were factors that influenced her decision.

The DDA had been functioning for two decades by then. It was established in 1957 in the wake of the Partition by the central government to ensure the planned expansion and development of Delhi. The predecessor of the DDA, the Delhi Improvement Trust (DIT), was established in 1941 on the recommendation of Arthur Parke Hume to manage urban congestion in the city following the shift of the capital from Calcutta to Delhi. Less than a decade later, the DIT was considered inadequate in its capacity to take care of a capital that was expanding both rapidly and haphazardly.

"Post-Independence, the first residential colonies of Delhi were built by the Ministry of Rehabilitation and some private developers in the 1950s. But development taking place was of an ad hoc nature and no one was responsible for providing road connectivity, infrastructure services like water, electricity and the like. Very often a house would be built but the residents would have to wait for five to ten years to get electricity and water connections," said A K Jain (74), who retired as commissioner of planning from the DDA. "Jawaharlal Nehru, being unhappy with the situation, believed that the capital needed to set an example of urban development."

Political scientist Sushmita Pati in a 2014 research paper noted that Nehru's idea of development hinged on the idea of a strong state. Consequently, "the DDA act of 1957, under which the DDA was set up, makes the public authority responsible for the acquisition of land and development of the city".

At H Block, Saket. The DDA has built over 100 residential colonies in Delhi which include Saket, Janakpuri, Pitampura, Paschim Vihar. Adrija Roychowdhury

Nehru's involvement in the making of the first master plan of Delhi (1962) under the DDA was significant. It was on his insistence that Albert Mayer of the Ford Foundation was brought in to prepare the plan along with the Town Planning Organisation.

Jagmohan, who became the commissioner of the DDA in the mid 1960s, was instrumental in the execution of the master plan. Pati in her paper wrote that Jagmohan believed that with the master plan, "the DDA took upon itself the project of building the 'ninth city' of Delhi which was twice the size of all seven cities that had come before". Apart from the city of Delhi, small towns and villages surrounding it were to be developed as the National Capital Region (NCR).

DELHI REWIND
Tracing the capital's post-Independence history

Initially, the DDA was provided Rs 5 crore with which it bought land from the agricultural communities, beautified it and sold it according to income groups or commercial agencies at a profit, which they later used to buy land again.

"The plan aligned with Nehru's socialist ideologies and prevented private players from land speculation," said Jain.

The first residential colony developed by the body was the Safdarjung Development Area. In the ensuing decades, more than 100 residential colonies have been built by the DDA, apart from the sub cities of Dwarka, Rohini and Narela. These include Pitampura, Janakpuri, Paschim Vihar among others. Further, more than 40 resettlement colonies were built for those dwelling in slums, a majority of which were created during Sanjay Gandhi's city beautification drive of the 1970s.

Jain, who joined the DDA as associate planner at the age of 28 in the mid 1970s, said that one of the reasons he wanted to be a part of the body was that the DDA had the reputation across the world as a model development agency.

"About 50 cities in India had later emulated the plan of the DDA. These included Bhopal, Bangalore and Jaipur," he said.

One of the biggest contributions made by the agency to the city, explained Jain, was to make available the opportunity of property ownership at an affordable cost to large numbers of migrants and salaried employees. "I remember my peon telling me how people in his village in Bihar would treat him with more respect after they found out that he had bought a flat in Delhi," Jain said.

Some flaws

But the DDA's plans were not without their flaws. Historian Sohail Hashmi explained that one of the first things done by the DDA was to place all of Shahjahanabad under the slum and JJ department. "That is the beginning of the decay of Shahjahanabad because the municipal authorities are not bound to provide many civic amenities in the slum and JJ areas," he said. "This was also when Shahjahanabad came to be referred to as the 'walled city'. It created an idea in the minds of Delhi people of it being a place that was walled off from the rest of the city."

Other criticisms against the body included the fact that its housing schemes had not met the goal of inclusive development as promised, that it only benefitted higher income groups, leaving behind large parts of Delhi's population. A 2014 report by the Centre for Policy Research noted that the nature of DDA's plans is such that "the city's poorest residents become squatters as the DDA acquires the land on which they live, yet they have few affordable housing options".

The ways in which people from slums were removed to resettlement colonies during the Emergency is yet again seen as a dark episode in the agency's history. In recent years, the agency has seen a drop in the number of applications for their projects.

Jain believes the reason for the lack of popularity is that the DDA has been unable to keep up with the times and meet the aspirations of a new India. "The model that was adopted 50-60 years back has to be totally changed. It has to build bigger houses with better quality construction and services," he said.

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JUNE 26, 2022

Complete TOD project before its deadline, says LG

Lieutenant governor VK Saxena was on his first visit to Karkardooma TOD site

Times News Network

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Saturday issued specific directions to Delhi Development Authority to stick to uncompromising structural safety in executing the city's first transit-oriented development (TOD) project in east Delhi's Karkardooma and take all progressive steps to fully integrate it with the neighbourhood and surroundings. He also asked the agency to complete the project before the scheduled deadline.

Spread over 37.4 hectares, the ₹1,168-crore DDA's flagship project comprises highrise residential complexes, commercial and office spaces, public utilities and multi-modal public transport facilities

Saxena was on his first visit to Karkardooma TOD site to take stock of the status and progress of work. The directions, said officials, were also issued to National Building Construction Corporation, which is executing the project for DDA.

This ambitious project, which is expected to change the skyline of the city and bring about unprecedented regeneration in the East Delhi area, has started to fructify after many delays caused due to pandemic-related lockdowns, pollution-related construction bans and regulatory clearances.

Spread over 37.4 hectares, the Rs 1,168-crore DDA's flagship project comprises high-rise residential complexes, commercial and office spaces, public utilities and multi-modal public transport facilities. The project has 30% green area.

Though the DDA's TOD policy, which is aimed at sustainable development around rapid transit facilities such as Metro, was notified in July 2015, it couldn't be implemented due to objections from the public against DDA regulations. In March 2017, the Union housing and urban affairs ministry directed DDA to review the policy. The execution finally started.

Work on the project finally started in September 2020 and is expected to be fully completed in September 2026. The residential component of the project comprising high-rise residential apartments and EWS housing, replete with all civic amenities, is expected to be completed by the middle of 2024. It will be one of the biggest residential complexes in the densely populated east Delhi with 4,358 flats, including 1,392 for the economically weaker section.

Appreciating the progress made so far, especially with regards to the construction of EWS housing towers and excavation work for the two-and three-bedroom apartment towers, the LG stressed that all measures required for structural safety of the buildings, including sufficiently strong retaining walls, piling, plinth and raft foundation be ensured without any compromise on quality.

He also asked the officers concerned to prepare and stick to a comprehensive prospective plan with regards to water supply, traffic management, power availability and seamless integration with the surroundings. He also advised the agencies to work in tandem and assured them of all help required at his level for inter and intra-department and agency coordination.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS ...... DATED---

नई दिल्ली
सोमवार
27 जून 2022

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 27 जून 2022

अनंगताल बावली फिर होगी गुलजार

एलजी ने किया दौरा, दो महीने में काम पूरा करने का निर्देश

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

अनंगताल बावली को एक बार फिर उसका पुराना रूप और आकर्षण वापस दिलाया जाएगा। मौजूदा समय में सीवर के पानी और कूड़े-कचरे से यह बावली भरी हुई है। रविवार को एलजी वी.के. सक्सेना ने अनंगताल बावली का दौरा किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों ने यहां काम भी शुरू कर दिया है। एलजी ने अधिकारियों को दो महीने में बावली को दोबारा पानी से भरने और पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। दौरे के दौरान एलजी के साथ डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, एएसआई और वन विभाग के अफसर भी मौजूद रहे।

इस बावली का निर्माण 11वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। निर्देश मिलने के बाद डीडीए और एएसआई ने अनंगताल बावली से गाद निकालने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अगले तीन से चार दिन में पूरे काम को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट में पूरे काम और इसको पूरा करने के समय के बारे में बताया जाएगा। मॉनसून से पहले गाद निकालने के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बारिश का पानी बावली में भर जाए। अनंगताल बावली करीब 45 फीट गहरी है

- आसपास बने सभी ऐतिहासिक निर्माणों को भी पुनर्जीवित करने का निर्देश
- जंगल में कॉन्फ्रेंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जगह तलाशने के लिए भी कहा
- संजय वन में कोकून पालन भी शुरू होगा

और इसमें पानी भरने से आसपास का भूजल स्तर बढ़ेगा। साथ ही यह बावली एक पर्यटक स्थल के रूप में राजधानी की शान बढ़ाएगी।

एलजी ने बावली के आसपास बने सभी ऐतिहासिक निर्माणों को भी पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अनंगताल बावली में एक ऐसी जगह की पहचान भी की गई है जो वॉटर रिजरवायर के तौर पर डिवेलप की जाएगी। एलजी ने बताया कि आसपास के होटलों और झुग्गियों से यहां आ रहे सीवर के पानी को रोक दिया गया है। साथ ही वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस जगह अतिक्रमण वाले हिस्से को खाली करवाया जाए। इसके अलावा इस जगह पर पौधारोपण के निर्देश भी दिए गए हैं। यहां से विलायती कीकर हटाकर फलों के पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। एलजी ने यह भी निर्देश दिए कि लोगों और बच्चों को सिल्क के उत्पादन के बारे में जागरूक करने के लिए संजय वन में कोकून पालन शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने जंगल में ऐसी जगह पहचानने को भी कहा जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस, फेस्टिवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन हो सके। इसके अलावा खेलों के लिए भी जंगल में जगह तलाशने की बात उन्होंने कही, खासतौर पर ऐसे पॉइंट जहां से कुतुब मीनार का क्लीयर व्यू लोगों को मिल सके।

हिन्दुस्तान

अनंग ताल बावली को विकसित करें

निर्देश

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अनंग ताल बावली (तालाब) दिल्ली को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर विकसित किया जाएगा। रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौका का निरीक्षण किया।

उपराज्यपाल ने कहा कि आज दिल्ली में 11वीं शताब्दी की विरासत संरचना कचरे, आस-पास के होटलों और झुग्गियों से निकलने वाले सीवेज के कारण गंदगी की एक बेसिन में बदल गई है। इसकी सूरत बदलने के लिए डीडीए, एएसआई और डीजेबी मिलकर काम करें। अधिकारी यह भी सुनिश्चित कराएं कि अनंग ताल के जीर्णोद्धार का काम तय समय सीमा के अंदर पूरा हो।

गाद निकालने का काम शुरू

उपराज्यपाल के निर्देश पर डीडीए ने अनंग ताल बावली तालाब की गाद निकालने का काम शुरू कर दिया है। वहीं एएसआई भी खुदाई का काम शुरू करने जा रही है। अगले तीन से चार दिन में तालाब के अंदर गंदगी निकलकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिससे कि बारिश सीजन आने पर तालाब के अंदर साफ पानी भर सके। उन्होंने कहा कि 45 फीट गहरे अनंग ताल के जीर्णोद्धार से भू-जल स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को सुंदर ढंग से विकसित किया जा सकेगा।

एलजी ने निर्देश दिया है कि अनंग ताल को दो महीने में होटल, झुग्गियों से आने वाले गंदगी पानी का बहाव से मुक्ति दिलाई जाए। अधिकारी सुनिश्चित करें कि यहां पर फलदार पौधों को लगाया है, जिससे विलायती किक्कर के पेड़ों की संख्या कम हो सके। यहां पर घने आरक्षित वन यानी संजय वन है, जो दक्षिण मध्य रिज का एक हिस्सा है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा किया गया था।

मनोज तिवारी ने सैनेटरी नैपकीन बांटे

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने रविवार को जगत पुरी विस्तार में डीडीए की ओर से निर्मित पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल और दिल्ली पुलिस आयुक्त की पत्नी अनु अस्थाना ने सांसद मनोज तिवारी के साथ 5000 जरूरतमंद महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन वितरित किए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED--------------------

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 27 जून, 2022

अनंगताल में खिलेंगे संस्कृति के 'फूल'

महरौली स्थित 11 वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनंगताल का निरीक्षण करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना • सौजन्य : राजनिवास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: झाड़ियों में तब्दील हो चुके ऐतिहासिक अनंगताल में अब न सिर्फ पक्षी कलरव करते हुए दिखाई देंगे, बल्कि यहां कला और संस्कृति के फूलों की बगिया भी खिलेगी। दरअसल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना 45 फीट की गहराई वाले अनंगताल को न सिर्फ भू-जल रिचार्ज की दृष्टि से जलाशय के रूप में विकसित करना चाहते हैं, बल्कि उनकी मंशा है कि इसके आसपास के इलाके में सुंदर फूलों वाले पौधे लगाए जाएं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्थान विकसित किया जाए, ताकि यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस संबंध में उन्होंने डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अनंगताल का पुराना स्वरूप दो माह में लौटाया जाए।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और एएसआइ के अधिकारियों के साथ रविवार को महरौली के संजय वन में स्थित 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनंगताल का दौरा किया। इस दौरान इसके जीर्णोद्धार के काम को पूरा करने का आदेश दिया। वर्तमान में यह ताल कचरा घर बन गया है। यहां सीवर का गंदा पानी व कूड़ा डाला जा रहा है। इस बावली का निर्माण 11वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय ने किया था। उपराज्यपाल को डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि यहां डी-सिल्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। मानसून की बारिश से पहले इसे साफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एएसआइ ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एएसआइ को 3-4 दिनों में अपनी कार्ययोजना उपराज्यपाल को सौंपनी है। उपराज्यपाल ने कहा कि 45 फीट गहरे अनंगताल के जीर्णोद्धार से न केवल भू-जल रिचार्ज होगा, बल्कि क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी। इसके आसपास सुंदर फूलों वाले पौधे लगाए जाने व पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इससे यहां देश-विदेश से लोग घूमने आएंगे। अनंगताल के आसपास के क्षेत्र में एक अन्य प्राकृतिक जगह को भी जलाशय में परिवर्तित किया जाएगा।

रोका गया गंदा पानी

अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि पास के होटलों और झुग्गियों से बावली में बहने वाले सीवर के पानी को अब रोक दिया गया है। इसके साथ ही वन क्षेत्र अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को जंगल के भीतर फलदार पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि संजय वन को रेशम उत्पादन की दृष्टि से भी विकसित किया जाए, ताकि स्कूली बच्चों को वहां ले जाकर इस बारे में जागरूक किया जा सके।

पिकनिक स्पाट भी बनाएं

उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा है कि जंगल के अंदर प्राकृतिक परिवेश में पिकनिक स्पाट बनाने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल भी विकसित किए जाएं। ताकि, इन स्थानों पर छोटे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के आयोजन किए जा सकें। इससे दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देश-विदेश के पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथ ही लालकिला और कुतुबमीनार देखने आने वाले लोग भी यहां पहुंचेंगे।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JUNE 27, 2022

LG tells officials to restore baoli in Sanjay Van

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Anang Tal Baoli (reservoir), an 11th century heritage structure, will regain its past glory under a project being undertaken by the Delhi Development Authority (DDA) in collaboration with the Archaeological Survey of India (ASI).

On Sunday, Delhi LG **VK Saxena** visited the baoli and Sanjay Van, which is part of the South Central Ridge. He was accompanied by senior officials of DDA, DJB, ASI, and the forest department during the visit. Raj Niwas, in a press statement, said the baoli had been reduced to a basin of muck, due to the decades-old sediment of garbage, and sewage discharge from the adjacent hotels and slums. The LG has instructed officials to bring the baoli back to life with fresh water within two months.

While DDA has begun de-silting work at the baoli, the ASI would also begin excavation work and submit a report in the next four days, along with a concrete timeframe to complete the restoration work. De-silting of the pond will be completed before the arrival of the monsoon so the pond is be filled with fresh rainwater.

He instructed the officials to identify green patches inside the forest that could be developed into the locations for organising recreational activities in the natural ambience in harmony with the surroundings.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान DATED नई दिल्ली सोमवार 27 जून 2022

मुख्य सात स्थानों में से तीन पर जलभराव की आशंका

खत्म करो इंतजार
मानसून की मुश्किलें 1

दिल्ली-एनसीआर में मानसून दस्तक देने को है। हर साल मानसून के समय लोगों को जलभराव के कारण मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता है। लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हिन्दुस्तान विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है। पहली कड़ी में दिल्ली में जलभराव के मुख्य स्थानों पर सरकार के दावों और उनकी हकीकत की पड़ताल करती हिन्दुस्तान टीम की रिपोर्ट...

इन स्थानों पर जलजमाव से सबसे अधिक दिक्कत

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के सात अंडरपास और फ्लाईओवर के नीचे जलभराव की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि अब दिल्ली में जलभराव वाली सात में से चार जगहों पर ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चार स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए काम किया गया है। इन स्थानों की समस्या को खत्म करने के लिए भी पिछले साल योजना तैयार कर ली गई थी, जिन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। जिन तीन जलभराव वाली जगहों पर काम अभी भी किया जा रहा है उनमें पुल प्रह्लादपुर, जखीरा फ्लाईओवर के नीचे, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की लोकेशन शामिल है।

पुल प्रह्लादपुर पर तीन साल में दो की जान गई : इस वर्ष मानसूनी बारिश से पहले ही दो दिनों की बरसात के दौरान पुल प्रहलादपुर अंडरपास दो बार जलमग्न हो चुका है। बीते तीन वर्षों में दिल्ली के अंडरपास में बारिश की वजह से हुए जलभराव के चलते दो लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 200 से अधिक छोटे-बड़े स्थान ऐसे हैं, जहां हर वर्ष जलभराव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है। मानसून आने से ठीक पहले दिल्ली सरकार के मंत्री बारिश के पानी का संचयन करने के लिए गड्ढे बनाने के दावे कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन दावों की हकीकत मानसून के समय पता चलेगी।

यहां तैयारी अधूरी

पुल प्रहलादपुर अंडरपास

पिछले साल मानसून के दौरान यहां कई बार जलजमाव हुआ। पीडब्ल्यूडी की ओर से यहां एक छोटा नाला बनाया जाना था, जो नहीं बना है। इससे यहां फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि, विभाग की ओर से यहां 7.5 लाख लीटर क्षमता का एक भूमिगत संप का निर्माण करवा दिया है और 600 हॉर्सपावर का एक स्थायी पम्प हाउस भी स्थापित हो गया है। वहीं भूमिगत संप व पंप हाउस का 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही यहां 7 अस्थाई पम्प भी लगाए गए हैं। यहां मॉनिटरिंग के लिए 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

अंडर जखीरा फ्लाईओवर

यहां पहले मानसून के दौरान रेलवे द्वारा बनाए गए अस्थायी कच्चे नाले से बरसात के मौसम में रेलवे लाइन पर कचरा अंडर पास में गिर जाता है। इसके कारण कटसंप जाम हो जाते है जिससे जलजमाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने रेलवे से संपर्क कर रेलवे लाइन के कचरे को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी स्क्रीन लगवाया है। ये कार्य करीब पूरा हो चुका है। जखीरा अंडरपास के आसपास के क्षेत्र में ड्रेन के मोडिफिकेशन का कार्य अभी बाकी है। नेहरू नगर/आनंद पर्वत से आने वाले स्टॉर्म ड्रेन को री-रूट किए जाने का काम भी अभी चल ही रहा है।

जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन

यहां जलजमाव को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्शन प्लान में सर्विस रोड के साथ एक नाले का निर्माण, मुकरबा चौक बाउंड से मुख्य सड़क के बीच पुराने एमसीडब्ल्यू ड्रेन का पुनर्निर्माण, रामगढ़ और महेंद्र पार्क आदि की ओर मुख्य सड़क के साथ एसडब्ल्यू ड्रेन की रीमॉडलिंग व स्थायी पम्प हाउस का निर्माण शामिल है, इन सभी जगहों पर निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह पूरा इलाका भूतल के हिसाब से नीचा है। आस-पास की कॉलोनियों का पानी बहकर यहां इकट्ठा होता है। इसके चलते इस बार भी यहां फिर से जलभराव होने की संभावना है।

यहां काम पूरा

मिंटो ब्रिज

एक साल पहले तक मिन्टो-ब्रिज के नीचे कम बारिश होने पर भी जलजमाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। इसे दूर करने के लिए पिछले साल कई स्थायी कदम उठाये गए और अप्रत्याशित बारिश होने के बावजूद यहां लोगों को जलजमाव का सामना नहीं करना पड़ा। इस साल अपनी तैयारियों को और बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार ने यहां अल्टरनेट ड्रेनज सिस्टम व आटोमैटिक वाटर पम्प स्थापित किया है।

कराला कंझावला रोड

यहां 3 स्थानों पर पीडब्ल्यूडी द्वारा ट्रॉली माउंटेड पंप लगाए जा रहे हैं साथ ही कराला कंझावला रोड को भी रिपेयर किया गया है। जिससे जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

इन जगहों पर मिलेगी जलभराव से मुक्ति

आईपी-एस्टेट रिंग रोड : डब्लूएचओ बिल्डिंग के सामने- रिंग रोड पर भी पिछले कुछ सालों से बारिश के वक्त जलजमाव की समस्या बनी रहती है। इसे खत्म करने के लिए यहां 9 पम्प लगाए गए हैं। साथ ही यहां पीडब्ल्यूडी 1.5 लाख लीटर का संप और पुराने आईपी पॉवर प्लांट से यमुना तक स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण कराया है।

"फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी करता हूं। तीन वर्षों से बारिश के वक्त ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता है। पुल प्रहलादपुर अंडरपास में इतना पानी भर जाता है कि डर लगता है डूब न जाऊं। हर बार सरकारी तैयारी की बात हम लोग सुनते हैं

विशाल शर्मा, बदरपुर निवासी

"मुझे जखीरा अंडरपास होते हुए पीरागढ़ी जाना होता है। बारिश के दिनों में जखीरा अंडरपास से निकलना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल जलभराव के कारण हुए गड्ढे में गिरने से पड़ोसी का पैर टूट गया था।

निशांत, आनंद पर्वत निवासी

"दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था करीब सौ साल पुरानी है। नई सीवरलाइन कम पड़ी है। इस कारण हल्की बारिश में ही छोटे नाले जाम हो जाते हैं और जलभराव की समस्या हो जाती है। इसके लिए दिल्ली को नए ड्रेनेज मास्टर प्लान की आवश्यकता है।

एस.के. जैन, सेवानिवृत्त टाउन प्लानर, डीडीए

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JUNE 27, 2022
TIMES

Walk Of Life: Footsoldiers Will Get Their Own Space

Work To Start At Key Sites For Barrier-Free Pavements, Street Furniture

DDA'S WALKABILITY PLANS FOR PRIORITY AREAS

400-500 metres Radius of seamless pedestrian connectivity around Metro station gates

50% Average number of commuters who access Metro stations on foot

60% Of all trips in the city are below 4 km, ideal for walking

40% Approximate road length in Delhi with no footpath

PILOT AREAS FOR WHICH 'WALK PLANS' HAVE BEEN PREPARED

1 ITO junction 2 INA market and Metro station 3 Hauz Khas-IIT Delhi 4 Nehru Place 5 Bhikaji Cama Place 6 Karol Bagh 7 Saket-Malviya Nagar 8 Kamla Nagar 9 Lajpat Nagar 10 Laxmi Nagar 11 Dwarka Sector-21 Metro Station 12 Adhchini, Aurobindo Marg 13 Old Delhi Railway Station 14 New Delhi Railway Station 15 Mandi House 16 Purana Qila, Pragati Maidan and Delhi zoo area 17 Inderlok Metro Station 18 Rajendra Place Metro Station 19 Azadpur Mandi and Metro station 20 Asaf Ali Road and JLN Marg area 21 Delhi University (North Campus and South Campus) 22 Uttam Nagar crossing 23 Chandni Chowk 24 All ISBTs

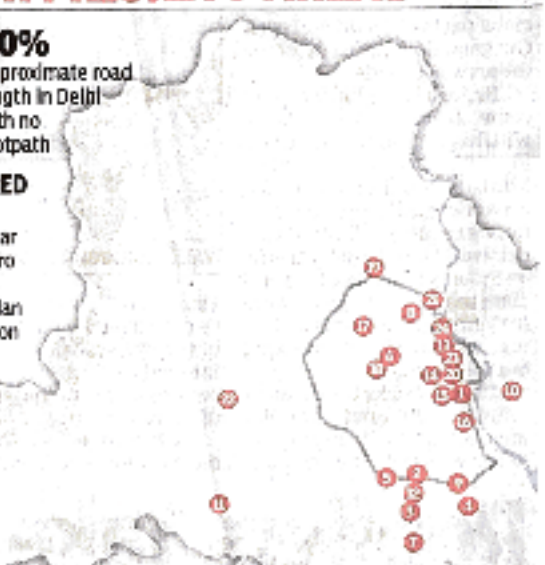

WALK PLAN GUIDELINES

Encroachment and barrier-free footpaths | Continuous pedestrian network | Street furniture like benches, **garbage bins**, information signage, etc | Vending zones | **Shaded tree plantation** | Safe at-grade crossings, foot overbridges and subways | Public plazas at no-vehicle zones | Safer subways through commercial activity, public art, street performances, etc | Pelican crossings | **Toilets** and drinking water facilities | Adequate street lighting

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Many busy locations in the city such as the ITO junction, office complexes like Bhikaji Cama Place and Nehru Place, hangout zones like Lajpat Nagar, INA Market, apart from roads around Delhi Metro stations, railway stations and interstate bus terminals are all set to become more pedestrian friendly. Delhi Development Authority is finalising customised "walk plans" for 24 such priority locations.

The walk plans aim at strengthening existing pedestrian infrastructure in areas where it's ill-maintained or inadequate and development in areas where it's not available. This includes providing better walking infrastructure at locations that see high footfall by removing encroachments, making footpaths barrier-free, apart from providing a continuous network.

A senior DDA official said out of 24 priority locations, final plans for seven locations were approved in the 66th governing body meeting of Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning & Engineering) Centre held on April 26. These locations include Nehru Place, Bhikaji Cama Place, Old Delhi Railway Station, Chandni Chowk, Saket-Malviya Nagar area, Inderlok Metro Station and Laxmi Nagar Metro Station and surrounding areas.

"We are preparing detailed reports with drawings and these should be completed soon. The approved walk plans will be shared with road-owning agencies like Public Works Department and Municipal Corporation of Delhi for implementation," said a DDA official. DDA itself would work on implementing walkability plans at Nehru Place and Bhikaji Cama Place.

Though "Regulations for Enhancing Walkability in Delhi" was notified on August 2, 2019, the preparations for walk plans got primarily delayed due to the Covid-19 outbreak. "DDA is preparing the detailed plans to ensure that the guidelines are followed thoroughly. The road-owning agencies will implement these plans in their respective areas," the official said.

DDA is following many overarching regulations, but all walk plans would be area specific. There are also plans to create a mobile application so that people can rate pedestrian facilities.

The walk plans would cover an influence zone of 400-500 metres around busy traffic intersections, markets, Metro stations, etc that see high pedestrian footfall. The objectives include increase in comfort and safety for pedestrians, comfortable access to last-mile connectivity from transport hubs, prioritising non-motorised private modes of transport and public transport in street design, etc.

The aim is also to reduce car use, which would lead to reduced congestion and pollution and more equity in the provision of comfortable public spaces and amenities to all sections of the society. The plans would include installation of 1020 second pedestrian signals and pelican crossings near schools. Other major pedestrian crossings would cater to children, elderly and the infirm.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला सोमवार, 27 जून 2022

अनंग ताल बावली को 2 माह में विकसित करें अधिकारी : एलजी

उपराज्यपाल ने डीडीए, एएसआई और डीजेबी के अधिकारियों संग किया दौरा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अनंग ताल बावली को दो माह के भीतर विकसित करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बावली सूखी है। इसकी तलहटी में नाममात्र पानी है। आसपास के होटलों और झुग्गियों से निकलने वाले सीवेज की गंदगी इसमें जमा है।

उपराज्यपाल ने रविवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण, एएसआई, दिल्ली जल बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ 11वीं शताब्दी के इस विरासत स्थल का दौरा किया। उन्होंने बावली को पुराने स्वरूप में वापस लाने और ताजे पानी से भरने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि इस संरचना की विरासत पहचान, विशेष कर मिट्टी के नीचे दबी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। अनंग ताल बावली घने आरक्षित संजय वन में स्थित है, जो कि दक्षिण मध्य रिज का एक हिस्सा है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा तैयार करवाया गया था।

अधिकारियों के साथ अनंगताल बावली का दौरा करते एलजी। अमर उजाला

बावली से गाद निकालने का काम शुरू

उपराज्यपाल के दौरे के तुरं[त] बाद ही डीडीए ने अनंग ताल बावली से गाद निकालने का काम शुरू कर दिया है, वहीं एएसआई भी जल्द खुदाई का काम शुरू कर देगा और अगले 3-4 दिनों में उपराज्यपाल को एक निश्चित समय सीमा में काम को पूरा करने की एक रिपोर्ट सौंपेगा। मानसून आने से पहले तालाब की डीसिल्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि तालाब में बारिश का ताजा पानी भरा जा सके। करीब 45 फीट गहरे अनंग ताल बावली के जीर्णोद्धार से न केवल भूजल रिचार्ज होगा, बल्कि क्षेत्र की सुंदरता में भी इजाफा होगा। यह जगह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी।

जंगल में फलदार पेड़ लगाने के निर्देश : उपराज्यपाल ने अधिकारियों को जंगल के भीतर फलदार पेड़ लगाने का निर्देश दिया ताकि विलायती कीकर के पेड़ों को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे संजय वन में कोकून पालन शुरू करें ताकि लोगों, विशेषकर स्कूली बच्चों में रेशम उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। सक्सेना ने अधिकारियों को जंगल के अंदर हरे भरे स्थान की पहचान करने के निर्देश दिए, जिन्हें विकसित कर प्राकृतिक परिवेश में छोटे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के आयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

पंजाब केसरी ▸ 27 जून, 2022 ▸ सोमवार

डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और एएसआई को दिए निर्देश

11वीं शताब्दी की अनंग ताल बावली का 2 माह में हो जीर्णोद्धार : एलजी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दक्षिणी दिल्ली के संजय वन के निकट बने 11वीं शताब्दी के अनंग ताल बावली का जीर्णोद्धार कर दो माह में पुराना रूप वापस लौटाया जाएगा। रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ बावली का दौरा किया और दो माह में इसके जीर्णोद्धार के काम को पूरा करने का आदेश दिया है। वर्तमान में यह बावली कचरा घर बन गई है। यहां सीवरेज का गंदा पानी व कूड़ा डाला जा रहा है। बता दें कि इस बावली का निर्माण 11वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा किया गया था। एलजी के आदेश के बाद डीडीए ने यहां डी-सिल्टिंग का काम करना शुरू कर दिया है और मानसून की बारिश से पहले इसे साफ कर दिया जाएगा। वहीं एएसआई ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एएसआई अगले 3-4 दिनों में अपने काम की रिपोर्ट एलजी को सौंपेंगे। इस मौके पर एलजी ने कहा कि 45 फीट गहरे अनंग ताल बावली के जीर्णोद्धार से न केवल भूजल रिचार्ज होगा, बल्कि क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी जिससे लोग यहां घूमने आ सकेंगे। एलजी ने बावली के आसपास पहले जैसी स्थिति फिर से बनाने का आदेश दिया है। अनंग ताल बावली के आसपास के क्षेत्र में एक अन्य प्राकृतिक जगह को भी एक जलाशय में परिवर्तित करने के लिए पहचाना गया है।

अनु अस्थाना ने महिलाओं को मिशन अनिवार्य के लिए किया प्रोत्साहित

सांसद तिवारी ने खजूर पार्क का लोकार्पण कर अभिनेत्री संग महिलाओं को बांटे सेनेटरी नैपकिन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने रविवार को जगत पुरी विस्तार में डीडीए द्वारा निर्मित पार्क का लोकार्पण किया और मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल, सांसद पत्नी सुरभी तिवारी, पुलिस आयुक्त की पत्नी अनु अस्थाना के साथ 5000 जरूरतमंद महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन वितरित किए।

लोगों को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने कहा की खजूर पार्क से जगतपुरी विस्तार के अलावा आसपास के हजारों लोगों को न सिर्फ उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा बल्कि शीघ्र ही इसी जगह पर बनने वाले उत्सव पंडाल से क्षेत्र को एक विकास का नया आयाम भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि बरसों अतिक्रमण की चपेट में रहेगी यह जमीन भूमाफिया से मुक्त होने के बाद क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगी। इस अवसर पर मौजूद लोगों की हौसला अफजाई करते हुए दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की पत्नी अनु अस्थाना ने कहा कि सांसद मनोज तिवारी का हर प्रयास ईमानदार और सार्थक है और जनहित के लिए समर्पित है। उन्होंने पार्क में ओपन एयर जिम लगाने का प्रस्ताव रखा जिसे सहजता से स्वीकार करते हुए पूरा करने का संकल्प सांसद मनोज तिवारी ने लिया। उनके आग्रह पर ही अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कई फिल्मी डायलॉग भी सुनाएं।

▸▸ सेनेटरी नैपकिन बांटते मनोज तिवारी, अनु अस्थाना व अमीषा पटेल।

27 जून • 2022 राष्ट्रीय सहारा

सांसद ने किया पार्क का लोकार्पण

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने जगतपुरी विस्तार में डीडीए की ओर से बनाये गये पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर उन्होंने अभिनेत्री अमीषा पटेल और पुलिस आयुक्त की पत्नी अनु अस्थाना के साथ 5000 जरूरतमंद महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन वितरित किए।

इस मौके पर अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जगतपुर विस्तार में आऊंगी। आने से पहले मुझे लगता था कि जाम होगा अव्यवस्था होगी, असुविधा होगी लेकिन सिग्नेचर ब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण ने मेरा आगमन सुगम कर दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो का निर्माण कार्य उत्तर पूर्वी दिल्ली को कई मायने में मुंबई के कई पास इलाकों से आगे जाने के लिए बढ़ाया गया कदम होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | JUNE 25, 2022

World Cities Summit in Singapore

AAP Govt accuses LG of sitting on file related to CM's Aug trip

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The tussle between the Arvind Kejriwal Government and Lieutenant Governor (L-G) Vinai Kumar Saxena is expected to intensify in the days to come as the former has accused Raj Niwas of not clearing a file that would allow Chief Minister Arvind Kejriwal to go to Singapore to attend the World Cities Summit scheduled for August 2-3. There was no immediate reaction from the L-G's office on the matter.

"Several files are stuck with the Lt-Governor for many days because of a lack of administrative experience. Among these is the file for the CM to go to Singapore to attend the World Cities Summit. That file has been pending for three weeks," a source said.

Kejriwal had said on June 2 that the High Commissioner of Singapore Simon Wong had invited him and he had accepted the invitation. Sources said that the file was sent to Saxena on June 7. Sources claimed that

even files on small issues are "stuck" with the L-G's office and it may affect governance and cause long delays in public interest work in Delhi.

According to protocol, any Minister including the Chief Minister or his Deputy, has to take approval from the Ministry of Home Affairs for official visits abroad. The file seeking such an approval is routed to the MHA through the L-G. The World Cities Summit is an exclusive platform for Government leaders and industry experts to address liveable and sustainable city challenges, share integrated urban solutions and forge new partnerships. It is jointly organised by Singapore's Centre for Liveable Cities and the Urban Redevelopment Authority.

Earlier this week, Deputy Chief Minister Manish Sisodia said that Saxena had permitted a probe into allegations of irregularities in the construction of Government hospitals without following the due procedure of taking permission from the Delhi Government.

He said that Saxena's predecessor, Anil Baijal, had concluded that it was a "frivolous" complaint and it was "politically motivated". "Now the new L-G has reopened the investigation by transferring it to the ACB," Sisodia said. Terming the case "false", he wrote to the L-G, requesting him to withdraw the permission given for the probe. He alleged that BJP leaders were trying to stall the construction of more Government hospitals in Delhi by filing frivolous complaints.

Earlier this month, some AAP MLAs including Atishi had accused the L-G of 'intruding' in the Delhi Government's work and 'conspiring' to derail democracy as he visited two Delhi Jal Board facilities and a sewage treatment plant on June 4.

After meeting Saxena, the MLAs, including former Delhi Minister Somnath Bharti alleged that the L-G told them that not just the Delhi Development Authority and the Delhi Police, but the "whole of Delhi is under his control". Bharti said that the L-G made this statement when the AAP MLAs raised several issues before him including some pertaining to law and order.

25-06-2022

पंजाब केसरी

भ्रष्टाचार मामले में एलजी ने दो अधिकारियों को किया निलंबित

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने दो और अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दो दिन पहले एलजी ने अन्य मामलों में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन को गलत तरीके से बेचने के आरोप में दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

सूत्रों के मुताबिक डीसी साहू, सब-रजिस्ट्रार-SA, हौज खास को एक निजी व्यक्ति की मिलीभगत से डीडीए की प्रमुख भूमि को ट्रांसफर करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की जालसाजी से जुड़े गंभीर कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए निलंबित किया गया है। दिल्ली में जोसिंग बोज टीटो मार्ग पर एक प्राइवेट पार्टी को कई करोड़ की जमीन दी गई। इसी मामले में क्षेत्र के तत्कालीन कानूनगो और रिकॉर्ड रूम प्रभारी रमेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एलजी को सांसदों और विधायकों से उक्त सब-रजिस्ट्रार के बारे में कई शिकायतें मिल रही थीं ये शिकायतें नागरिकों और समूहों के रूप में की गई थीं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिनमें संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए घूस की मांग, दस्तावेजों से छेड़छाड़ और मनमानी शामिल थे, उनके संज्ञान में लाए गए। जांच करने पर यह पाया गया कि मौजूदा मामले में सब-रजिस्ट्रार ने क्षेत्र के कानूनगो प्रभारी के साथ आपराधिक मिलीभगत करके न केवल यह दिखाने के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे कि डीडीए की 1,250 वर्ग गज जमीन फ्री होल्ड थी बल्कि फरवरी, 2022 में एक बिक्री विलेख भी दर्ज किया था।

जमीन को गलत तरीके से बेचने के आरोप में हुई कार्रवाई

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------------------------------DATED---------------------

दैनिक भास्कर | नई दिल्ली, शनिवार 25 जून, 2022

हेराफेरी • डीडीए की प्राइम लोकेशन पर 1,250 वर्ग मी. की जमीन के जाली दस्तावेज बनाने का आरोप

भ्रष्टाचार पर एलजी का बड़ा वार, फर्जीवाड़ा करने वाले 2 और अफसरों को सस्पेंड किया

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दो और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दो दिन पहले उपराज्यपाल ने अन्य मामलों में चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नार्थ जिला के बाद अब दक्षिणी दिल्ली के राजस्व विभाग हौजखास में सब रजिस्ट्रार-5ए के पद पर तैनात डोसी साहू पर तत्कालीन कानूनगो और रिकॉर्ड रूम प्रभारी रमेश कुमार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के भ्रष्टाचार के जीरो टोलरेंस नीति के तहत उनके अनुशंसा पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने निलंबित कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल को चुने हुए प्रतिनिधियों और क्षेत्र के लोगों ने उपराज्यपाल को चिराग दिल्ली में जोसिप बीज टीटो मार्ग के प्राइम लोकेशन पर 1250 वर्ग मीटर की कई सौ करोड़ रुपए के सरकारी जमीन को सब रजिस्ट्रार द्वारा प्राइवेट आदमी को बेचने की शिकायत की थी। जिस मामले की उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए थे।

डीएम सोनालिका जीवनी के समय का गोरखधंधा

जांच में सामने आया है कि रजिस्ट्रार डोसी साहू ने तत्कालीन कानूनगो और रिकॉर्ड रूम प्रभारी रमेश कुमार के साथ मिलकर तत्कालीन डीएम साउथ सोनालिका जीवनी के कार्यकाल दौरान साहू ने जमीन का जाली दस्तावेज तैयार किया था। रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन 1250 वर्ग मीटर है। यह जमीन डीडीए से यार्ड फ्री होल्ड था, लेकिन फरवरी, 2022 में एक बिक्री विलेख भी दर्ज किया गया था। इस जमीन को प्राइवेट आदमी के नाम पर पंजीकरण के लिए साहू के द्वारा रिश्वत की बड़ी रकम की भी मांग की शिकायत मिली थी। बता दें कि इसकी सूचना संवाददाता ने डिवीजनल कमिश्नर संजीव खिरवार से 12 मई को 8:15 मिनट पर इस बारे में उनका पक्ष मांगा था। मामला सोनालिका जीवनी के होने के कारण खिरवार ने इस मामले में चुप्पी साध ली थी।

500 करोड़ की सरकारी जमीन को एसडीएम ने गैर कानूनी तरीके से निजी लोगों को बेचा: भारद्वाज

नई दिल्ली | आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में तैनात एसडीएम पर 500 करोड़ की सरकारी जमीन को एसडीएम ने गैर कानूनी तरीके से निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है। विधायक व मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने खुद प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने उनकी अध्यक्षता में इस मामले की जांच की है। विशेषाधिकार समिति ने पाया कि तत्कालीन डीएम सोनालिका जीवनी के कार्यकाल में एसडीएम ने फर्जी कागजात तैयार लोगों को सरकारी जमीन बेचा। इस मामले में तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार को भ्रष्टाचारियों को बचाने और तथ्य छुपाने पर डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार को नोटिस दिए हैं पर खिरवार ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। जिसके लिए डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार को अवमानना के नोटिस भी दिए गए हैं और उन पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि विशेषाधिकार समिति ने इस भ्रष्टाचार की जांच की लेकिन एलजी कार्यालय ने इस बात को छिपाने की कोशिश की। उपराज्यपाल कार्यालय ने चार पदाधिकारी और अफसर सस्पेंड करने का पूरा ब्यौरा मीडिया को नहीं बताया।

एसडीएम के भ्रष्टाचार पर प्रेस वार्ता करने की क्यों जरूरत पड़ी

▶ सौरभ भारद्वाज बताएं कि एसडीएम के 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर प्रेस वार्ता करने की क्या जरूरत पड़ गई। राजस्व विभाग दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत जमीन से लेकर कोरोना के दौरान भोजन, टेंडर तक की कंट्रोलर फाइनेंस द्वारा रोकी गई कई सौ करोड़ रुपए के पेमेंट के रूप में मुताबिक टैक्स सर्विस को एक वकील की राय लेकर संजीव खिरवार से पास करवा दिया है।
–सुनील यादव, उपाध्यक्ष, भाजपा दिल्ली प्रदेश

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला PA नई दिल्ली | शनिवार, 25 जून 2022 ----DATED----

जमीन रजिस्ट्री में अनियमितता के आरोप में सब रजिस्ट्रार और कानूनगो निलंबित

भ्रष्टाचार पर उपराज्यपाल का सख्त रवैया

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में जमीन की रजिस्ट्री के मामले में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त सब रजिस्ट्रार और कानूनगो को निलंबित कर दिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अनियमितता में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में उपराज्यपाल ने कदम बढ़ाते हुए यह कार्रवाई की है।

सूत्रों का कहना है कि गांव इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की करोड़ों की जमीन को एक व्यक्ति की मिलीभगत से हस्तांतरित करने के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सब रजिस्ट्रार (5-ए, हौजखास) डीसी साहू को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में गंभीर कदाचार करते हुए दक्षिण दिल्ली के जोनिंग ब्लॉक टीटो मार्ग में जमीन के हस्तांतरण के दौरान क्षेत्र के तत्कालीन कानूनगो रमेश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। उपराज्यपाल को सांसदों और विधायकों समेत क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों और समूहों की तरफ से लगातार सब रजिस्ट्रार की शिकायतें मिल रही थीं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत संपत्तियों के पंजीकरण के लिए रिश्वत की मांग, दस्तावेज जुड़े मामलों सहित कई और मामले संज्ञान में लाए गए थे।

सूत्र बताते हैं कि जांच में सामने आया कि इस मामले में सब-रजिस्ट्रार ने निजी व्यक्तियों और क्षेत्र के कानूनगो प्रभारी के साथ आपराधिक मिलीभगत से 1250 वर्ग मीटर की जमीन के जाली दस्तावेज भी बनाए थे। डीडीए से संबंधित फ्री होल्ड जमीन को फरवरी, 2022 में एक सेल डीड भी पंजीकृत किया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दो अधिकारियों को निलम्बित करने की सिफारिश के बाद 21 जून को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। ब्यूरो

500 करोड़ की जमीन को एसडीएम ने गैरकानूनी तरीके से बेचा था

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी उपराज्यपाल के एसडीएम को निलंबित करने का मामला उजागर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने उपराज्यपाल के चार एसडीएम निलंबित करने के कारणों का खुलासा किया। समिति के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से लोगों को बेचने का उन्होंने खुलासा किया था। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने और तथ्य छिपाने पर मंडलायुक्त को नोटिस दिए थे, लेकिन उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बात को छिपाने की कोशिश की। अब तक उपराज्यपाल कार्यालय ने चार एसडीएम और अन्य अधिकारी निलंबित करने के कारण उजागर नहीं किए।

दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष और आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि विधानसभा में उन्होंने प्रश्नकाल में जमीन घोटाले का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय भ्रामक सूचना देने से बचें। उन्होंने जनवरी माह के दौरान विधानसभा सत्र में राजस्व विभाग से झंगोला गांव स्थित सरकारी भूमि से संबंधित एक सवाल लगाया था, जिसका जवाब विभाग ने नहीं दिया था। इसके बाद सदन में विरोध प्रकट किया गया था। इस पर सभापति ने सभी प्रश्न विशेषाधिकार कमेटी को दिए और जनवरी से लेकर अब तक कमेटी जांच कर रही थी। इस मामले में दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने मंडलायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को बुलाया। इस दौरान पता चला कि कई लोग विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी उनकी संपत्ति सरकार के अधीन थी। इस संपत्ति का किसी को स्वामित्व नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद कई एसडीएम ने सैकड़ों करोड़ की जमीन भ्रष्टाचार करके लोगों को सौंप दी। भारद्वाज ने कहा कि यह जमीन 500 बीघा से अधिक है। ऐसे में कम से कम 500 करोड़ रुपये की जमीन का मामला है। कई एसडीएम ने गलत तरीके से आदेश पास किए। इस मामले में वह मंडलायुक्त के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। इस मामले में करीब दो महीने पहले अजीत ठाकुर एसडीएम को निलंबित किया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | JUNE 25, 2022

2 more Govt officials suspended over graft charges

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Two more officials were suspended on Thursday, separately by Delhi Lieutenant Governor (L-G) Vinai Kumar Saxena and Delhi Chief Secretary Naresh Kumar, in connection with alleged corruption concerning illegal sale of Government land, two days after the L-G sacked three officials in the same case.

A Sub-Registrar of the Delhi Government's Revenue Department has been suspended for "fraudulent" transfer of a land parcel to a private party.

Delhi Chief Secretary Naresh Kumar suspended Hauz Khas Sub-Registrar DC Sahoo on Wednesday for the transfer of prime Delhi Development Authority (DDA) land worth several crores to a private party on Josip Broz Tito Marg in Chirag Delhi. Disciplinary action has been initiated against the Sub-Registrar and some more officials involved in the land transfer may also face action, sources said.

The land parcel measuring 1,250 square yard, valued around Rs 30 crore, was situated near the BRT corridor. A complaint was lodged and action was taken after the matter came to the knowledge of locals of the area.

The land is owned by the village panchayat and meant for community use but it was first transferred to an individual and then to a private entity in a "fraudulent" manner, sources added.

The matter was brought to the notice of Delhi Assembly's petition committee after which records were scrutinised and it was found that the land was transferred to a cultivator although no cultivation had taken place on it.

"Action was taken against the Sub-Registrar as he had registered the sale deed of the land 'without proper verification' that would have revealed it was Government land," sources added. Sources said that Ramesh Kumar the then Kanoongo of the area and record room in-charge has also been put under suspension in the same case. "The Delhi Government and Raj Niwas had been receiving several complaints about the said Sub-Registrar from MPs and MLAs cutting across party lines as indeed individual citizens and groups living in that area. Serious charges of corruption that included blatant demand of bribes for registering properties, subversion of documents and high handedness were brought to his notice," Delhi Government officials said. On June 21, the L-G suspended three officials — two Sub-Divisional Magistrates and one Deputy Secretary in the Chief Minister's Office — over charges of corruption in transfer of evacuee properties to private entities between 2015 and 2021. Senior officials who asked not to be named said the four officials suspended by the L-G were posted as SDM Alipur at different times and allegedly passed orders giving away ownership of evacuee land, vested with the Government of India, to private entities.

House panel began probe against graft in Jan: AAP

LG misleading people by penalising four officers as action has already been initiated, says Bhardwaj

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Aam Aadmi Party (AAP)-led Delhi Government on Friday accused the newly-appointed Lieutenant Governor (L-G), VK Saxena, of misleading people by penalising four Delhi Government officers on charges of financial irregularities even though a committee formed by the Delhi Assembly Speaker has already probed the matter and action has been initiated.

AAP spokesperson Saurabh Bhardwaj said that the committee had summoned the then Divisional Commissioner Sanjeev Khirwar for protecting the corrupt and hiding the facts and later after a thorough probe the case was forwarded to Raj Niwas for further action through the controlling Union Home Ministry.

Addressing a press conference, Bhardwaj said that earlier, during the Assembly session, the Revenue Department was asked a question that "Is it true that in Jhangola Village of North Delhi, Government land worth several crores of rupees was sold to private entities illegally?' but the department did not answer this question and there was a ruckus in the House.

"These questions were later transferred to the Privileges Committee by the Speaker, and from January until now, the committee has been investigating the matter," said Bhardwaj. "During investigation, the committee several times called upon then Divisional Commissioner, Khirwar and later the current Divisional Commissioner KR Meena.

We also called DM North and their senior officers and found out that several pieces of land that are evacuee properties of families that left India during time of Partition were sold illegally," said Bhardwaj.

"This land was under the custody of the Central Government, and it is also known as custodial land. This land cannot be transferred to any other person under the Delhi Land Reforms Rules, 1954 and its ownership cannot be given to anyone else," alleged Bhardwaj.

"Now while investigating the matter, the committee has found out that it is over 500 bighas – and in very simplistic terms, it is a matter of over Rs 500 crore. A series of SDMs have over time managed to illegally sell this land off to private builders," he said.

"Around two months ago, an SDM named Ajit Thakur was suspended in the matter. Three SDMs named Devendra Sharma, PC Thakur and Harshit Jain were also suspended. The Committee also found that a few more ADM and DMs were indulged in financial irregularities," said Bhardwaj.

"I was the first person to raise this matter. I asked a starred question in the Legislative Assembly and a committee of the Assembly conducted an investigation on the matter," claimed Bhardwaj.

"Hauz Khas Sub-Registrar DC Sahu and another official Kanoongo got suspended and it was projected as if the L-G took the action. The reality is that the Committee on petitions which took the action. For the L-G's information, I want to tell him that this matter is of my constituency," said Bhardwaj.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर | नई दिल्ली, रविवार 26 जून, 2022

एलजी का निर्देश • वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों को कर के दायरे में लाएं

एमसीडी की सभी सुविधाओं को 31 जुलाई तक ऑनलाइन कर दिया जाएगा : सक्सेना

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सभी सुविधाओं को पूरी तरह से जुलाई महीने तक ऑनलाइन कर दिया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर निगम को 31 जुलाई आईटी-सक्षम बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने एमसीडी द्वारा किए जा रहे आईटी कार्यों में पहल की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी नागरिक केन्द्रित सेवाएं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, संपत्ति कर, ई-म्यूटेशन, भवन योजना स्वीकृति, ले-आउट अनुमोदन, लाइसेंस, कनवेंजन और पार्किंग शुल्क सहित अन्य सभी को घर बैठे उपलब्ध कराया जा सकता है। इन सभी को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सेवाओं में मानवीय हस्तक्षेप न हो। इससे न केवल काम समय पर होगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के डेटा बेस को ऐसे सरकारी विभागों से जोड़ने का आदेश दिया जो खाद्य सुरक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ और अन्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान कराते हैं ताकि जन्म या मृत्यु होने पर नाम स्वतः लाभार्थी के नाम का अपडेशन या डीलिशन हो सके।

घरों में पैदा होने वाले बच्चों की होगी सूची तैयार

उप-राज्यपाल ने घरों में पैदा होने वाले बच्चों की सूची तैयार करने को कहा है। उन्हें बताया गया कि दिल्ली में 26% बच्चों का जन्म अस्पताल/नर्सिंग होम में न होकर घर पर ही होता है। उप-राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक ऐसे वार्ड की रैंडम ढंग से जांच करें जहां घर में होने वाली जन्मदर सबसे ज्यादा हो और साथ ही इसके पीछे के कारणों का भी पता लगाएं। उप-राज्यपाल ने कहा कि शहर की सभी संपत्तियों-वाणिज्यिक और आवासीय को कर के दायरे में लाया जाए, ताकि एमसीडी की आय में बढ़ोतरी हो और निगम बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि 65% क्षेत्र में रिहायशी संपत्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और लोग सम्पत्तिकर के दायरे से पूरी तरह से बाहर हैं। बैठक में निगम के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार तथा निगमायुक्त ज्ञानेश भारती उपस्थित थे।

कड़कड़डूमा की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना का काम समय से पहले हो पूराः एलजी

नई दिल्ली | उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को कड़कड़डूमा में दिल्ली की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) परियोजना का निर्माण स्थल पर कार्यों का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने डीडीए और एनबीसीसी के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा से पहले कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।

अमर उजाला | नई दिल्ली | रविवार, 26 जून 2022

समय से पहले पूरा हो टीओडी प्रोजेक्ट : एलजी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिल्ली के पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) प्रोजेक्ट को तयशुदा समय से पहले पूरा करें।

निर्माण में सुरक्षा इंतजामों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना है। साथ ही, नजदीकी क्षेत्रों के साथ टीओडी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, जिससे आवाजाही बाधित न हो। इससे पहले वीके सक्सेना ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट के कामों की मौजूदा स्थिति व उसकी प्रगति का जायजा लिया।

कड़कड़डूमा स्थित टीओडी प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते उपराज्यपाल। - अमर उजाला

दरअसल, एक ही कैंपस के भीतर बहुमंजिला आवास व दफ्तर समेत दूसरी व्यावसायिक इकाइयां विकसित करने और आम लोगों की दैनिक जरूरतों को कैंपस के भीतर ही पूरा करने के मकसद से डीडीए कड़कड़डूमा में टीओडी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कोविड महामारी जनित लॉकडाउन, प्रदूषण संबंधित निर्माण प्रतिबंधों की वजह से काम देरी से शुरू हुआ। करीब 25.47 हेक्टेयर में फैले प्रोजेक्ट का 30 फीसदी हिस्सा हरित क्षेत्र होगा। इसका काम सितम्बर 2021 में शुरू हुआ। इसके सितम्बर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, सभी सुविधा से लैस आवासीय कॉम्प्लेक्स का काम 2024 व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवास 2023 तक पूरे होंगे।

संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए : मुआयना करते हुए उपराज्यपाल ने निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस टावर और 2-3 बेडरूम वाले आवासीय कॉम्प्लेक्स के कार्य की प्रगति की तारीफ की। उन्होंने जोर दिया कि इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को जलापूर्ति, यातायात प्रबंधन, बिजली की उपलब्धता और नजदीकी इलाकों के कैंपस के साथ निर्बाध एकीकरण की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। सलाह दी कि अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर उन्होंने खुद भी दखल देने का भरोसा दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी ▸ 26 जून, 2022 ▸ रविवार

लापरवाही द्वारका रोड नंबर-202 के नजदीक की समस्या

टूटी लोहे की रेलिंग दे रही दुर्घटनाओं को दावत

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : द्वारका सेक्टर-7 स्थित सड़क के बीचोंबीच डिवाइडर पर लगी टूटी हुई लोहे की रेलिंग दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। एक स्कूल के पास द्वारका रोड नंबर-202 के साथ लगी हुई लोहे की रेलिंग टूट कर सड़क पर आ चुकी है जो आने जाने वाली वाहनों को दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है।

मधु विहार आरडब्ल्यूए के प्रधान रणबीर सिंह सोलंकी ने बताया कि महीने भर से यही स्थिति बनी हुई है लेकिन डीडीए के किसी अधिकारी और कर्मचारी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो इसके चपेट में आकर कोई भी वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इससे उसकी जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि द्वारका में ऐसे कई जगह हैं जहां डिवाइडर के बीचोंबीच लगी लोहे की रेलिंग एक तरफ झुक गई है। लेकिन कई महीने

सड़क किनारे टूटी हुई रेलिंग।

बीत जाने के बाद भी इसे सीधा नहीं किया गया। सोलंकी ने कहा कि इस बाबत डीडीए के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया है।

खुला नाला हादसे को दे रहा न्यौता

एशिया की सबसे बड़ी उपनगरी द्वारका की हालत बदहाल हुई है। इस बात का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि द्वारका के बड़े-बड़े नाले कई महीनों से टूटे पड़े हुए हैं, कई ऐसे भी नाले हैं जिसे टूटे हुए एक साल से भी ऊपर का समय हो गया है। जिसे अभी तक नहीं बनाया जा सका है। रोड नंबर-201, जो एयरपोर्ट से नजफगढ़ को जोड़ता है। इस मुख्य मार्ग में कई जगह ऐसे मिल जाएंगे जहां नाले टूटे पड़े हुए हैं। सेक्टर-2 धीरपुरा के पास का नाले का बड़ी हिस्सा टूट गया है। एक साल से ऊपर समय बीतने के बाद भी इसे ढका नहीं गया है। वहीं एनएसयूआईटी के दोनों तरफ के नाले टूटे हुए हैं। इस पर डीडीए के किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष ने इस बाबत कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है। लेकिन अधिकारी इस मामले को कोई सुध नहीं ले रहे हैं।

टीओडी का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करें अधिकारी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने डीडीए और एनबीसीसी के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कड़कड़डूमा स्थित दिल्ली की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) परियोजना का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि संरचनात्मक बिल्डिंग सुरक्षा पर कोई समझौता न हो साथ ही आसपास के क्षेत्रों के साथ परियोजना का निर्बाध एकीकरण करने के लिए हर तरह के कदम उठाए जाएं।

बता दें कि विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को कार्यों की स्थिति और प्रगति का जायजा लेने के लिए निर्माण स्थल का दौरा किया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना जो कि शहर के स्काइ लाइन को बदलने के साथ-साथ पूर्वी दिल्ली में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी, का कार्य महामारी संबंधित लॉकडाउन, प्रदूषण संबंधित निर्माण प्रतिबंधों और नियामक मंजूरियों के कारण देरी से शुरू हुआ। 25.47 हेक्टेयर में फैले इस परियोजना में जहां न्यूनतम 30 प्रतिशत हरित क्षेत्र होगा, का कार्य अंततः सितंबर 2021 में शुरू हुआ और इसके सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

कड़कड़डूमा टीओडी प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल का निरीक्षण करते एलजी विनय कुमार सक्सेना।

परियोजना के आवासीय कम्पोनेन्ट में हाई एंड आवासीय अपार्टमेंट और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग शामिल है, जो कि सभी नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे और इनका कार्य क्रमशः 2024 तथा 2023 में पूरा कर लिया जाएगा।

उपराज्यपाल ने कहा कि इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय जैसे पर्याप्त रूप से मजबूत रिटेनिंग वाल, पाइलिंग, पिलिंग और रैफ्ट नींव के निर्माण में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 26 JUNE, 2022 PAPERS DATED

Complete city's 1st TOD proj before scheduled deadline: L-G Saxena

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Lt Governor V K Saxena on Saturday instructed the DDA and NBCC to complete Delhi's first transit oriented development (TOD) project at Karkardooma before scheduled deadline, a statement said.

He had gone to take stock of the status and progress of work at the site of the project in east Delhi, according to the statement issued by the Raj Niwas.

The Lt Governor issued specific directions to the DDA and NBCC to complete the project "before the scheduled deadline, stick to uncompromising structural safety and take all prospective steps to fully integrate the upcoming complex with the neighbourhood and surroundings," it said.

Work on this project spread over 25.47 ha with minimum 30 per cent green area, had started in September 2021 and is expected to be fully completed in September 2026, it said.

This ambitious project that will change the skyline of the city and bring about unprecedented regeneration in east Delhi area had started to fructify after much delay, caused due to the COVID-19 pandemic-induced lockdowns, pollution related construction bans and regulatory clearances, the statement said. The residential component of the project, comprising high rise apartments and EWS housing facility, replete with all civic amenities is expected to be completed by the middle of 2024 and 2023 respectively, it added.

Appreciating the progress made so far especially with regards to the construction of EWS housing towers and excavation work for the two-bedroom and three-bedroom apartment towers, the LG stressed that all measures required for structural safety of the buildings, including sufficiently strong retaining walls, piling, plinth and raft foundation be ensured without any compromise on quality.

Saxena also asked the officers concerned present on the occasion to prepare, and stick to a comprehensive prospective plan with regard to water supply, traffic management, power availability and seamless integration with the surroundings.

He also advised the authorities to work in tandem and assured them of all help or intervention required at his level for inter or intra-department or agency coordination.

Top officials of the Delhi Development Authority and National Buildings Construction Corporation, among others were present during his site visit.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU
SUNDAY, JUNE 26, 2022

Expedite TOD project at Karkardooma: L-G

Saxena instructs MCD to make all services requiring public interface IT-enabled

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Lieutenant Governor V.K. Saxena has asked the Delhi Development Authority and NBCC to complete the Capital's first transit-oriented development (TOD) project at Karkardooma before the deadline, the Raj Niwas said on Saturday.

L-G Vinai Kumar Saxena

This development comes after Mr. Saxena's visit to the project site in east Delhi, during which he took stock of the work's progress, while directing the agencies to stick to "uncompromising structural safety" and take steps to fully integrate the upcoming complex with the neighbourhood.

Deadline: Sept. 2026

Spread across 25.47 hectares with a minimum green area of 30%, the project took off in September 2021; it is scheduled for completion by September 2026.

The TOD is an urban planning concept that involves mixed-use development, which includes residential, business and leisure spaces within walking proximity of each other, along with existing and upcoming public transport infrastructure.

According to Raj Niwas, the project's residential component comprising EWS housing and high-rise residential apartments is expected to be completed by the middle of 2023 and 2024, respectively.

The L-G has also instructed the Municipal Corporation of Delhi to make all services that require public interface IT-enabled and online by July 31, according to an official statement on Saturday.

Mr. Saxena said services like property tax, advertisement, building plan sanction, layout approval, licenses, conversion and parking charges were so far being carried out in a piecemeal manner. He added that the move will ensure effective and timely delivery, "minimise inconvenience and harassment of people" and curtail inefficiency and corruption.

नई दिल्ली । रविवार • 26 जून • 2022 | सहारा

निर्धारित समय पर पूरा करें टीओडी प्रोजेक्ट : एलजी

डीडीए के ईस्ट दिल्ली हब प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे उप-राज्यपाल

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'ईस्ट दिल्ली हब' का शनिवार को उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने निरीक्षण किया। कड़कड़डूमा स्थित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के तहत डीडीए एनबीसीसी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। निरीक्षण के दौरान एलजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिल्डिंग की संरचना सुदृढ़ होने के साथ ही सुरक्षित हो एवं नागरिकों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाए। इस मौके पर डीडीए एवं एनबीसीसी के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी मुझे अंतर एवं बाह्य विभागीय/ एजेंसी समन्वय के लिए उनकी जरूरत होगी, वह समुचित सहायता एवं हस्तक्षेप करेंगे।

उप-राज्यपाल ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के बाद बैठक में अधिकारियों से कहा कि टीओडी योजना के तहत दिल्ली का यह पहला प्रोजेक्ट है। अधिकारी इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता का खास ध्यान रखें। गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र के साथ निर्माण एकीकरण करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। उप-राज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे पूर्वी दिल्ली में काफी बदलाव दिखेगा। कोरोना महामारी की वजह से

बिल्डिंग की संरचना सुदृढ़ होने पर दिया जोर

टीओडी योजना के तहत दिल्ली का पहला प्रोजेक्ट, पूर्वी दिल्ली में दिखेगा बदलाव

प्रोजेक्ट शुरू करने में देरी हुई है। यह प्रोजेक्ट 25.47 हेक्टेयर जमीन पर फैला है और इसमें कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा हरित क्षेत्र होगा। सितम्बर, 2026 तक प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से बहुमंजिला (हाईराइज) आवासीय अपार्टमेंट होंगे। इसमें 75 फीसद ईडब्ल्यूएस हाउस भी शामिल हैं।

उन्होंने हाउसिंग टावर्स में 2/3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट पर जोर देते हुए कहा कि निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र में पर्याप्त रूप से मजबूत रिटेनिंग वाल, पाइलिंग, प्लिंथ एवं रैफ्ट नींव के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। निर्माण स्थल पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने जलापूर्ति, यातायात प्रबंधन, बिजली की उपलब्धता एवं परिवेश का विशेष ध्यान रखा जाए। उप-राज्यपाल ने दोनों विभागों को मजबूत सामंजस्य के साथ काम करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी मुझे अंतर एवं बाह्य विभागीय/ एजेंसी समन्वय के लिए उनकी जरूरत होगी, वह समुचित सहायता एवं हस्तक्षेप करेंगे। बैठक में डीडीए एवं एनबीसीसी के आला अधिकारी मौजूद थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | JUNE 26, 2022

DATED

Bring all properties under tax net to improve financial conditions, LG directs MCD officials

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Saturday directed the Municipal Corporation of Delhi (MCD) to bring all properties — commercial as well as residential — under the tax net to improve its financial conditions so it can provide better services to people.

Expressing concern that 65 per cent of the geographical area of Delhi did not pay any property tax, the Lt Governor directed officials to simplify the forms for property tax registration and ensure its Aadhaar linkage.

In a review meeting on Friday, the Lt Governor also directed the civic body to make all its services related to property tax filing, assessment, recovery, mutation and building plan sanction among others IT-enabled by July 31.

The Lt Governor instructed the MCD officials to explore all possible ways of revenue enhancement and reiterated his resolve to turn the "red financial status of the MCD to a robust green".

The Lt Governor's direction came amid plans of the MCD to collect tax from major commercial establishments located in unauthorised colonies in Delhi.

Property tax remains one of the main sources of revenue for the MCD. The total property tax collection for 2021-22 was Rs 2,032 crore. Data from MCD shows that around 11.50 lakh properties paid the tax during 2021-22.

According to the officials, there is hardly any tax collection from unauthorised colony areas so the civic body is considering to tap big commercial properties in such localities and realise tax from them. Saxena said that non-payment of property tax by as many as 65 per cent of the owners was an unfortunate, unfair and unviable situation.

"The entire city, and not only the 35 per cent of residents of 11 lakh houses in regularised colonies, was availing of amenities and services offered by the municipal corporation. It would only be fair and justified that all pay property tax at differential rates as per their respective self-assessed financial status," he said.

In this regard, the LG asked officials to take the people and resident welfare associations (RWAs) on board and address their concerns. Such partnership with the people, he said, will not only facilitate honest self-assessment on part of the assesses but also increase tax collection.

An MCD official said the civic body is planning to widen its tax net to boost revenue generation under which it is also likely to review its property tax collection system in a way that it does not put burden on people. The MCD earlier this month had decided to hike the transfer duty by 1 per cent on properties priced above Rs 25 lakh across the city to improve its financial condition. During the review meeting, the Lt Governor ordered the linking of this database to government departments that provide services related to food security, pensions, maternity benefits and other welfare schemes to enable automatic updating or deletion of names upon birth or death.

Complete Delhi's first transit-oriented development project before deadline: LG

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

In another review meeting, Lt Governor Vinai Kumar Saxena on Saturday instructed the DDA and NBCC to complete Delhi's first transit-oriented development (TOD) project at Karkardooma before scheduled deadline.

According to a statement issued by the Raj Niwas, he had gone to take stock of the status and progress of work at the site of the project in east Delhi.

The Lt Governor issued specific directions to the DDA and NBCC to complete the project "before the scheduled deadline, stick to uncompromising structural safety and take all prospective steps to fully integrate the upcoming complex with the neighbourhood and surroundings," it said.

Work on this project spread over 25.47 ha with minimum 30 per cent green area had started in September 2021 and is expected to be fully completed in September 2026, it said.

This ambitious project that will change the skyline of the city and bring about unprecedented regeneration in east Delhi area had started to fructify after much delay, caused due to the COVID-19 pandemic-induced lockdowns, pollution-related construction bans and regulatory clearances, the statement said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU
SUNDAY, JUNE 26, 2022

Suspension of DDA officials dents morale of JJ cluster residents

Action over 'substandard' work leaves slum rehab project beneficiaries in a fix

MUNEER KHAN
NEW DELHI

Days after the Delhi Development Authority (DDA) suspended two of its assistant engineers over "substandard" work at the urban body's in situ slum rehabilitation project at Kalkaji Extension, the residents of Bhoomiheen Camp (JJ cluster), who have been allotted flats in the project, remain worried about the quality of their future homes.

According to a senior DDA official and other sources, the suspensions came on the directions of Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena following his inspection of the site on June 11. Sources said the L-G found the work done in the flats to be "substandard and incomplete".

Shattered hopes: Broken windows at the DDA's slum rehabilitation project (right) at Kalkaji Extension. • R.V. MOORTHY

Long wait

The news about the suspensions and the "substandard" quality of the flats has left the residents of the JJ cluster in a fix about what to do next. While a number of allottees told *The Hindu* that they have waited too long and would accept what comes their way, some beneficiaries said they were, in fact, reconsidering the option to move in.

Sapan Shah, 59, a beneficiary of the slum rehab project, said the recent developments have killed all his excitement about moving into the newly built homes.

"They should have looked into the quality of the houses beforehand or at least at the planning stage. Now the time has passed. We are paying out of our pocket for these homes. We don't have a choice now, we must adjust to what we get," said Mr. Shah, who has been residing at the JJ cluster since 1982.

Sharing a similar view, Parimal Mandal, a resident who runs a small shop at the camp, said since 2011, when the project was first conceived, the families at the JJ cluster have undergone multiple surveys to prove their eligibility and over 50% of them have received allotment-cum-demand letters so far.

₹1.42 lakh per flat

According to the DDA, the flats will be allotted upon the payment of ₹1,42,000 per allottee, which includes ₹30,000 as maintenance charge for a period of five years.

Under the project, the DDA has constructed 3,024 flats – each of which have two rooms, a washroom, a kitchen and a balcony – for slightly over 2,800 households at the JJ cluster.

In February, the DDA conducted the first draw of lots in which allotment letters were issued to 673 households. Last week, the DDA conducted a second draw of lots for 903 eligible households.

At the project site, visited by *The Hindu*, broken windowpanes and incomplete fittings were spotted outside multiple flats, which measure slightly over 25 square metres, while the interiors of a sample flat were complete and intact.

"One has to understand that the people living in this (Bhoomiheen) camp are very hesitant and economically weak. Such developments lead to major worries. For them, it is about having proper housing and they now fear that they may face more problems after moving into the flats," said a resident, adding that he is having second thoughts about paying for the flat.

'Residents misled'

Reacting to the concerns raised by the JJ cluster residents, the senior DDA official denied that the work was substandard and said the beneficiaries were being misled with rumours about the construction quality. On the incomplete fittings, the official said there were only a few flats where they were yet to be installed.

"During the L-G's visit, he first inspected the sample flat and was quite satisfied with it. Upon inspecting the other flats, he noticed that some fittings such as switches and other facilities had not been installed. The officials tried to explain that they will be installed once the homes are allotted, but the L-G was unhappy with the condition of the flats," said the official.

All JJ cluster beneficiaries will be allotted the flats this year itself, said the official, adding that the project is likely to be inaugurated by a dignitary from the Union government.

"We are going to start issuing the possession letters from next week and we have also reduced the paperwork for the beneficiaries to avoid any hassle. Once they make the payment, vacate their homes in the slum cluster and get a demolition slip, the entire cluster will be removed and the land will be utilised by the DDA," said the official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
ESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | MONDAY | JUNE 27, 2022

Develop Anang Tal Baoli as a jewel of Delhi: LG

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor (L-G) Vinai Kumar Saxena on Sunday inspected the heritage Anang Tal Baoli at Sanjay Van and issued directions to restore and develop it into a "jewel of Delhi".

The L-G, who was accompanied by officials of the Delhi Development Authority (DDA), Delhi Jal Board (DJB), and the Archeological Survey of India (ASI), further directed them to identify green patches inside the forest that can be developed into locations for small national and international conferences, festivals, cultural events and other recreational activities. According to a statement issued by Raj Niwas, the L-G instructed that the 'baoli' be brought back to life with fresh water within two months. He also stressed that the restoration should be carried out strictly keeping in mind the preservation of the heritage identity of the structure, particularly its features buried underground.

He directed that an MoU be signed among the DDA, ASI, World Monument Fund (WMF), India, and Tata Consultancy Services Foundation (TCSF) within a week to carry out comprehensive restoration of the heritage 'baoli', the statement said.

Anang Tal Baoli (pond), an 11th-century heritage structure of Delhi, has been reduced to a basin of muck due to the decades-old sediment of garbage and sewage discharge from the adjacent hotels and slums. It is nestled in the reserve forest "Sanjay Van", which is a part of the south central ridge. It was constructed in the 11th century by Anangpala II, the Tomar ruler who is said to have inhabited the city of Delhi around his citadel of Lal Kot -- one of the earliest known forts in Delhi, the statement claimed.

"The DDA has immediately begun de-silting of the Anang Tal Baoli and the ASI too, will begin the excavation work and submit a report in the next 3-4 days along with a concrete time-frame to complete the restoration work. De-silting of the pond will be completed before the arrival of monsoon so that the pond could be filled with fresh rainwater," the statement said.

The restoration of the 45-foot deep Anang Tal Baoli will not only recharge the groundwater but will also add to aesthetic beauty of area. It has the potential of eventually developing into a tourist destination.

millenniumpost
NEW DELHI | MONDAY, 27 JUNE, 2022

'DEVELOP IT INTO A JEWEL OF DELHI'

L-G orders restoration of Anang Tal Baoli

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Sunday inspected the heritage Anang Tal Baoli at Sanjay Van here, and issued directions to restore and develop it into a "jewel of Delhi", an official statement said.

The L-G, who was accompanied by officials of the Delhi Development Authority (DDA), Delhi Jal Board (DJB), and the Archeological Survey of India (ASI), further directed them to identify green patches inside the forest that can be developed into locations for small national and international conferences, festivals, cultural events and other recreational activities.

According to the statement, the L-G instructed that the 'baoli' be brought back to life with fresh water within two months. He also stressed that the restoration should be carried out strictly keeping in mind the preservation of the heritage identity of the structure, particularly its features buried underground.

The L-G instructed that the 'baoli' be brought back to life with fresh water within two months

He directed that an MoU be signed among the DDA, ASI, World Monument Fund (WMF), India, and Tata Consultancy Services Foundation (TCSF) within a week to carry out comprehensive restoration of the heritage 'baoli', the statement said.

Anang Tal Baoli (pond), an 11th-century heritage structure of Delhi, has been reduced to a basin of muck due to the decades-old sediment of garbage and sewage discharge from the adjacent hotels and slums.

It is nestled in the reserve forest "Sanjay Van", which is a part of the south central ridge.

It was constructed in the 11th century by Anangpala II, the Tomar ruler who is said to have inhabited the city of Delhi around his citadel of Lal Kot — one of the earliest known forts in Delhi, the statement claimed.

"The DDA has immediately begun de-silting of the Anang Tal Baoli and the ASI too, will begin the excavation work and submit a report in the next 3-4 days along with a concrete time-frame to complete the restoration work. De-silting of the pond will be completed before the arrival of monsoon so that the pond could be filled with fresh rainwater," the statement said. The restoration of the 45-foot deep Anang Tal Baoli will not only recharge the groundwater but will also add to the aesthetic beauty of the area. It has the potential of eventually developing into a tourist destination.

The L-G gave specific instructions to restore every heritage structure in the vicinity of the baoli, underlining that this would create awareness among the large number of people visiting this forest.

During the inspection, the L-G was informed that sewage water flowing into the baoli from adjacent hotels and jhuggis has now been stopped and a chunk of encroached land inside the forest area has been cleared.

The L-G directed the officials to carry out plantation of fruit-bearing trees within the forest so as to outnumber the Vilayati Keekar trees. He also told officials to start cocoon rearing in Sanjay Van so as to create awareness among people, particularly school children about silk production, the statement said.